www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 21 || लखनऊ
मंगलवार
21 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
मौसम
सूर्योदयः 05:37
सूर्यास्तः 06:33
अधिकतमः 41°00
न्यूनतमः 27°00

पेज 03

विशेष समाचार | कृत्रिम बुद्धिमत्ता : सुविधा का वरदान... >> पेज 02 | यूपी में 64 आईएएस का ट्रांसफर... >>पेज 04 | साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की दूसरे टी...

फास्ट न्यूज

सुभाषचंद्र बोस को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने की मांग खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने और आजाद हिंद फौज (INA) को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली PIL खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को "न सुधरने वाला" बताया और सख्त टिप्पणी की।

हादसा रेस्क्यू

जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसा, 21 की मौत

उधमपुर। जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस कगोत के पास सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।

हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग रामनगर से उधमपुर में अपने रोजाना के काम पर जा रहे थे। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हैदराबाद-हुबली फ्लाइट 2 घंटे हवा में चक्कर काटती रही

बेंगलुरु । हैदराबाद से हुबली जा रही Fly-91 एयरलाइन की एक फ्लाइट रविवार को खराब मौसम के चलते 2 घंटे हवा में ही चक्कर काटती रही। खराब मौसम की वजह से प्लेन में सवार पैसेंजर्स को तेज झटके महसूस हुए, जिससे वे घबरा गए। सोशल मीडिया में वायरल VIDEO में पैसेंजर रोते हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिख रहे हैं।

केजरीवाल को कोर्ट से झटका

जस्टिस शर्मा ही करेंगी सुनवाई, आवेदन खारिज, कहा- निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अपना जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। सुनवाई को दौरान केजरीवाल ने कहा, मैडम अगर मेरा जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया तो यह न्याय के प्रति लापरवाही होगी। अदालत में अखिल भारतीय देवता परिषद के कार्यक्रमों में न्यायमूर्ति के शामिल होने पर कहा कि वह महिला

केजरीवाल ने 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपनी दलील खुद रखी थी।

दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जिसमें उन्होंने जूनियर वकीलों और अन्य बार के सदस्यों को संबोधित किया था। केवल अरविंद केजरीवाल की आईडियोलॉजी से सहमति न रखने के चलते यह आरोप गलत है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा मेरा न्यायिक करियर 34 वर्षों का रहा है। >> (शेष पेज 04 पर)

अदालत ने की सख्त टिप्पणी

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यदि किसी न्यायाधीश का फैसला ऊपरी अदालत द्वारा बदला जाता है तो किसी भी प्रतिवादी को यह कहने का हक नहीं है कि आमुख जज फैसला करने योग्य नहीं हैं। जज की क्षमताओं पर फैसला इसकी उच्च अदालत करती है ना की प्रतिवादी।

कैच-22 रणनीति पर अदालत सख्त

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि आवेदक ने अपने लिए 'विन-विन' या कैच-22 की स्थिति बना ली है। यदि अदालत खुद को अलग करती है तो उसके दावे सही ठहरेंगे, और यदि नहीं करती है तो वह फिर भी फैसले पर सवाल उठा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी रणनीतियों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया और संस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा है। >> (शेष पेज 04 पर)

राहुल की दोहरी नागरिकता केस से हाईकोर्ट जज हटे

सीबीआई जांच- एफआईआर का आदेश दिया, फिर पलटा था

निर्णय

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। सोमवार को जज ने यह फैसला याचिकाकर्ता की पोस्ट से नाराज होकर लिया है। याचिकाकर्ता ने पोस्ट किया था कि यदि आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, अन्यथा आपको जेल जाना होगा। हालांकि उसने अपने पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। दरअसल 17 अप्रैल को जज ने

राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। अगले ही दिन अपना फैसला बदलते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। >> (शेष पेज 04 पर)

जज ने पूछा- पीठ पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित

सोमवार को लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, जज सुभाष विद्यार्थी ने याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर की उन सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें धमकी दी गई थी। जज ने याचिकाकर्ता से पूछा, पीठ पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित है? अदालत के खिलाफ बोलना सही है? जज ने कहा, आवेदक ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट का इस्तेमाल किया।

'मोदी झूठों के सरदार उनके खाने दिखाने के दांत अलग'

वह चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं : खड़गे

प्रचार

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता/चेन्नई । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल के कूचबिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी 'झूठों के सरदार' हैं। वह चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा- अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो वह ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए और सबसे पूछे कि इसे कैसे लागू करें? लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया ताकि दिखा सके कि उसे महिला आरक्षण की परवाह है। सच तो यह है कि मोदी के खाने और दिखाने के अलग-अलग दांत हैं।

ममता बोलीं- मोदी ने प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बंगाल के ही मेदिनीपुर में कहा- आज बंगाल में कोई हुमायूं कबीर बोलता है कि यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप की जगह है क्या। >> (शेष पेज 04 पर)

योजना : अखिलेश यादव का फोकस स्टार्टअप, एआई और समग्र स्वास्थ्य पर

'विजन इंडिया समिट' के जरिए नए भारत की रूपरेखा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की परिकल्पना पर आधारित "विजन इंडिया समिट" देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई। यह श्रृंखला 16 नवंबर 2025 को बेंगलुरु से शुरू होकर 13 दिसंबर 2025 को हैदराबाद, 17 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर, 15 मार्च 2026 को मुंबई और 11 अप्रैल 2026 को जयपुर में संपन्न हुई।

इन आयोजनों में बुद्धिजीवियों, मीडिया विशेषज्ञों, युवाओं और उद्यमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भविष्य के भारत को लेकर अपने विचार साझा किए।

"विजन इंडिया" अभियान को

PDA यानी Plan (योजना), Develop (विकास) और Ascent (प्रगति) के सिद्धांत पर आधारित बताया गया।

अखिलेश यादव ने इसे एक ऐसा मंच बताया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलकर देश के लिए रचनात्मक और परिवर्तनकारी विचार प्रस्तुत कर सकें। हैदराबाद में आयोजित समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक के उपयोग पर विशेष चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और AI का उपयोग इन पर नियंत्रण के लिए

- "विजन इंडिया समिट" का उद्देश्य देश में प्रगतिशील, व्यावहारिक और समावेशी विकास की दिशा तय करना है।
- यह पहल युवाओं, तकनीक और सामाजिक संतुलन के जरिए एक नए भारत की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

जरूरी है। साथ ही उन्होंने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने और तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। >> (शेष पेज 04 पर)

बेंगलुरु समिट: स्टार्टअप्स और युवाओं पर जोर

श्रृंखला की शुरुआत बेंगलुरु से हुई, जहां मुख्य फोकस स्टार्टअप्स और युवाओं पर रहा।

अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में मौजूद चुनौतियां ही नवाचार के लिए अवसर हैं।

उनका कहना था, "हर समाधान एक स्टार्टअप है। देश की बड़ी आबादी और समस्याएं नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण देती हैं।" उन्होंने स्टार्टअप्स को सिर्फ मुनाफे का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बताया।

सड़कों और छतों पर खड़े होकर लोगों ने किया बुलडोजर बाबा का दीदार

'ममता दीदी 15 साल बहुत खेल लिया अब विकास का समय है'

- योगी का बंगाल में क्रेज, देखने को उमड़ी भीड़
- कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने बंगाल को किया कंगाल
- यूपी में माफिया की हड्डी-पसली तोड़ता है बुलडोजर

रैली

तमसा संकेत, एजेंसी

पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे सीएम योगी

लखनऊ/पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबर्दस्त क्रेज दिख रहा है। एक ओर चिलचिलाती धूप में योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें देखने-सुनने और एक झलक पाने को हजारों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को गारबेटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप लोढ़ा के पक्ष में हुई चुनावी रैली में भी यही नजारा दिखा, जब दीवारों, वाहनों और घरों की छतों पर खड़े होकर लोगों ने योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना और योगी-योगी की गूंज से उनका बंगाल की धरा पर स्वागत किया।

योगी आदित्यनाथ ने भी नौजवानों, किसानों, महिलाओं से आह्वान किया कि जिस बंगाल को कांग्रेस, कम्युनिस्टों और तृणमूल कांग्रेस ने कंगाल किया है, उसे इन पार्टियों की अराजकता से मुक्त कराइए।

तृणमूल की अराजकता से मुक्त अब डबल इंजन सरकार लाने जा रहा पश्चिम बंगाल

सीएम ने बंगाल के राष्ट्रनायकों की धरा बताया, कहा कि जब तुष्टिकरण की पराकाष्ठा और टीएमसी सरकार की गुंडागर्दी चरम पर हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आया है।

कभी लीडर की भूमिका में रहा बंगाल लूजर की भूमिका में हो गया है। भारत की आर्थिक उन्नति का आधार रहा बंगाल तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस व कम्युनिस्टों के लूटतंत्र का शिकार होकर कंगाल हो गया है।

यूपी में हैं ऐसी सड़कें कि हाथ पर रखे कप से पानी भी नहीं छलकेगा

सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जयश्रीराम बोलने पर ममता दीदी को परेशानी होती है। सड़कों पर इफ्तार पार्टी कराने वाली ममता दीदी ने राम नाम, दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन, शोभायात्रा पर बैन लगा दिया है।

2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी अराजकता, गुंडागर्दी, सड़कों पर नमाज और इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन यूपी में 9 साल से डबल इंजन सरकार चल रही है, तबसे नो कर्फ्यू, नो दंगा है, यूपी में सब चंगा है। >> (शेष पेज 04 पर)

यूपी में माफिया की हड्डी-पसली को चकनाचूर कर देता है बुलडोजर

सीएम ने कहा कि यूपी में गोहत्या, लवजेहाद, लैंडजेहाद नहीं हो सकता। माफिया व गुंडों ने हिमाकत की तो बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली को चकनाचूर कर देता है।

टीएमसी का मतलब टेरर, माफियाराज व करप्शन है। इसे केवल भाजपा सरकार ही समाप्त कर सकती है। न गोहत्या होने देंगे और न ही हिंदू को बंटने देंगे। उन्नति के लिए बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य करना है।

बंगाल में राम का नाम लेने से चिढ़ती हैं ममता दीदी और यूपी में बन गया भव्य राम मंदिर

सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में सड़कों पर इफ्तारी और नमाज नहीं होती है। मस्जिद से अजान भी नहीं सुनाई देती।

यूपी में हर तरफ खुशहाली है। ममता दीदी बंगाल में राम का नाम लेने पर चिढ़ती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आसमान को छूता भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया।

हर भारतीय को सीना तानकर खड़े होने और मर्यादा की प्रेरणा देने वाला राम मंदिर बताता है कि आस्था झुकती, रुकती, टूटती नहीं है। बस चुनौती का सामना करने की इच्छाशक्ति हो।

वहां विधर्मियों के हौसले पस्त हुए।

अंबेडकरनगर डीएम का तबादला, अनुपम शुक्ला बने गाजीपुर के डीएम

यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस

फेरबदल

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अंबेडकरनगर। प्रशासनिक फेरबदल के तहत अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को स्थानांतरित कर गाजीपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

वहीं, पर्यटन विभाग में तैनात रहीं ईशा प्रिया को अंबेडकरनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। नए जिलाधिकारी के आने के बाद जिले में प्रशासनिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिलेगा। >> (शेष पेज 04 पर)

कार्यकाल रहा लगभग एक वर्ष

अनुपम शुक्ला ने 21 अप्रैल 2025 को अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी का पदभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों पर फोकस किया। >> (शेष 04 पर)

- पर्यटन विभाग की ईशा प्रिया को अंबेडकरनगर की नई जिलाधिकारी की जिम्मेदारी

ईशा प्रिया को अंबेडकरनगर की जिम्मेदारी

पर्यटन विभाग में कार्यरत रही ईशा प्रिया को अब अंबेडकरनगर जिले की नई जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंबेडकरनगर जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे प्रमुख कार्य उनके कार्यक्षेत्र में रहेंगे।

कोटा में सड़कों को ठंडा करने के लिए पानी छिड़का

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ। देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर जारी है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ में लगातार चौथे दिन लू का कहर देखने मिल रहा है। राजस्थान के कोटा में दिन का तामपान 42C रहा। सड़कों को ठंडा करने के लिए नगर निगम ने टैंकरों से पानी का छिड़काव करवाया।

महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान सबसे ज्यादा 45C रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों शहर रविवार को देश के सबसे गर्म शहर रहे।

बिहार के बक्सर में सोमवार को गर्मी के कारण 10 स्टूडेंट स्कूल में बेहोश हो गए। बक्सर में आज पार 42C पर पहुंच गया है। इधर, जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई।

बर्फबारी के कारण मुगल रोड, श्रीनगर-कारगिल रोड और बांदीपोरा-गुरेज रोड समेत कई सड़कें बंद हैं।

राजस्थान में एचपीसीएल रिफाइनरी में लगी आग

काबू पाया गया, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

बाड़मेर/बालोतरा, राजस्थान । राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में सोमवार दोपहर 2 बजे भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाली दो यूनिट में लगी।

यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रहीं। करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की

- कच्चा तेल फिल्टर करने वाली दो यूनिटों में लगी आग
- पचपदरा रिफाइनरी में गुजरात से आना है कच्चा तेल

लागत से बनी इस रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्घाटन करने वाले थे। >> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

परिसीमन का जटिल प्रश्न

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने के बाद पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यह लगभग तय है कि यह दौर हाल-फिलहाल थमने वाला नहीं है। कहना कठिन है कि आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं को किसका नैरेटिव सही जान पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने और महिला आरक्षण को लागू करने के तौर-तरीकों पर तकरार करने से किसी को और विशेष रूप से लोकसभा एवं विधानसभाओं में अपने लिए 33 प्रतिशत सीटों की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

अब जबकि प्रधानमंत्री ने गत दिवस राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण को लागू कराने के अपने इरादे से वे डिगे नहीं हैं एवं उनके हौसले बुलंद हैं और विपक्ष भी यह कह रहा है कि उसका विरोध महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के फार्मूले और परिसीमन से है, तब फिर उचित यह होगा कि इस जटिल प्रश्न का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्ष सहमति कायम करने की दिशा में आगे बढ़ें। परिसीमन के प्रश्न को और अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता। संवैधानिक आवश्यकता यह कहती है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात रही कि 1971 की जनगणना के बाद 1976 में परिसीमन की प्रक्रिया इस कारण फ्रीज कर दी गई, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क था कि वे अपनी आबादी कम करने में सफल रहे हैं और परिसीमन से उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

विडंबना यह रही कि 1976 में 25 वर्ष के लिए फ्रीज किए गए परिसीमन को 2001 में 25 और वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अब जबकि यह अवधि पूरी हो गई है, तब मौजूदा जनगणना के बाद परिसीमन तो कराना ही होगा, अन्यथा संविधान की इस मूल भावना का निरादर होगा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। विपक्षी दलों ने भले ही परिसीमन पर आपत्ति जताकर महिला आरक्षण की राह रोक दी हो, लेकिन यदि अगली जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उससे दक्षिण के राज्यों को तो राजनीतिक रूप से अधिक नुकसान ही होगा। ऐसे में उचित यही होगा कि सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाकर परिसीमन किया जाए ताकि लोकसभा के सभी सदस्यों को लगभग समान संख्या में लोगों के प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। यदि दक्षिण के राज्यों के जनसंख्या आधारित परिसीमन के विरोध को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो इससे उत्तर भारत के राज्यों के हितों की कहीं अधिक अनदेखी होगी और यह भी उचित नहीं होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : सुविधा का वरदान या मूल्यों का संकट

> वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है। इसके माध्यम से झूठी सूचनाओं का निर्माण, नकली चित्रों और ध्वनियों का सृजन तथा जनमत को प्रभावित करने के प्रयास तेजी से बढ़े हैं।

मानव सभ्यता के विकास का इतिहास यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हर नई तकनीक अपने साथ संभावनाओं और संकटों का एक द्वंद्व लेकर आती है। आज का समय भी इसी द्वंद्व से गुजर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हो रही नवीन तकनीक ने जीवन को सरल, तीव्र और सुविधाजनक बनाया है, किंतु इसके साथ ही यह मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती भी बनकर उभर रही है। समाज के चिंतकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेतृत्व ने समय-समय पर इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और हाल ही में पोप लियो 14 द्वारा व्यक्त आशंकाओं ने इस चिंता को वैश्विक विमर्श का केंद्र बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस तकनीक का उपयोग नैतिक मर्यादाओं से परे जाकर किया गया, तो यह विश्व में विभाजन, भय, हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। यह चेतावनी केवल एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस गहरी चिंता का संकेत है जो आज पूरी मानवता के भीतर कहीं न कहीं विद्यमान है। तकनीक अपने आप में न तो नैतिक होती है और न ही अनैतिक, किंतु उसका उपयोग उसे किसी भी दिशा में ले जा सकता है। चुनावी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। जब कोई मतदाता यह समझ ही नहीं पाता कि जो वह देख रहा है या सुन रहा है वह सत्य है या निर्मित भ्रम, तब उसकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। आज सोशल माध्यमों पर ऐसी अनेक घटनाएँ सामने आती हैं, जहाँ किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं के साथ दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता। यह केवल व्यक्तिगत भ्रम नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर विश्वास की संरचना को कमजोर करने वाला प्रवाह है। जब झूठ और सत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समाज में संशय, अविश्वास और अस्थिरता का वातावरण बनता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक और चिंताजनक पक्ष है साइबर अपराधों में इसका बढ़ता उपयोग। आज अपराधी किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करके उसके परिचितों को धोखा देने में सक्षम हो गए हैं। परिवार के सदस्य या अधिकारी बनकर धन की ठगी करना अब अत्यंत सरल हो गया है। इस प्रकार की घटनाओं ने अनेक लोगों की जीवन भर की कमाई को पल भर में समाप्त कर दिया है। यह केवल आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा की भावना पर गहरा आघात है। वित्तीय क्षेत्र में भी इस तकनीक का दुरुपयोग गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। स्वचालित हमलों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाया जा सकता है। यदि इस प्रकार के हमले व्यापक स्तर पर होते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत हानि तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर सकते हैं। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब नियामक संस्थाएँ इन जटिल तकनीकों की गति और स्वरूप को समझने में पीछे रह जाती हैं।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह तकनीक पूरी तरह निर्दोष नहीं है। विशाल आंकड़ा केंद्रों की स्थापना, ऊर्जा की अत्यधिक खपत, तथा खनिज संसाधनों का दोहन-ये सभी प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों की बढ़ती मांग पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय शोषण दोनों को जन्म देती है। इस प्रकार यह तकनीक केवल सामाजिक या नैतिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चुनौती भी बन रही है। इन सभी चिंताओं के बीच यह समझना आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यह आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है और चिकित्सा, शिक्षा, आपदा प्रबंधन तथा उत्पादन के क्षेत्र में इसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के स्वरूप में है। यदि इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाए, तो यह एक वरदान सिद्ध हो सकती है।

इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इसके विकास और उपयोग के लिए स्पष्ट और सशक्त नियम बनाए जाएं। सरकारों और संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग पारदर्शी, सुरक्षित और उत्तरदायी तरीके से हो। कंपनियों को अपने तंत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री की पहचान और नियंत्रण संभव हो सके। साथ ही नागरिकों की जागरूकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता के बिना कोई भी समाज इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता। लोगों को यह समझना होगा कि जो कुछ वे देख या सुन रहे हैं, वह हमेशा सत्य नहीं हो सकता। सत्यापन की प्रवृत्ति को विकसित करना समय की आवश्यकता है। नैतिकता के स्तर पर यह भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े निष्पक्ष और उच्च गुणवत्ता वाले हों। यदि आधार ही पक्षपाती होगा, तो परिणाम भी पक्षपाती होंगे। इससे सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए निष्पक्षता, पारदर्शिता, गोपनीयता और उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को इसके विकास का आधार बनाना होगा।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तकनीकी विकास हमारी परंपराओं और मूल्यों के साथ संतुलन बनाए रखे। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का डिजिटलीकरण और संरक्षण इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, किंतु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग सम्मानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। साररूप में यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक शक्तिशाली साधन है, जो मानव जीवन को नई दिशा दे सकता है। किंतु यदि इसे नैतिकता से अलग कर दिया जाए, तो यह उसी गति से विनाश का कारण भी बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक के विकास के साथ-साथ अपने नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करें। विज्ञान और मानवीय संवेदना के बीच संतुलन ही वह मार्ग है, जो हमें सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है।

ललित गर्ग

प्राचीन भारतीय प्रशासनिक...

प्रदीप कुमार वर्मा

सिविल सेवा : देश की प्रशासनिक व्यवस्था की 'रीढ़'

भारतीय संवैधानिक प्रावधानों में तीसरी स्तंभ कहे जाने वाले कार्यपालिका के तहत सिविल सर्विस वह सेवा है, जो देश की सरकार के सार्वजनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारत में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा ,भारतीय विदेश सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह शामिल हैं।

हमारे देश में भारतीय सिविल सेवक न केवल नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वे नीतियों को आकार देने, निर्णय लेने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में प्रशासनिक संचालन,विकास योजनाओं का क्रियान्वयन,कानून व्यवस्था बनाए रखने,प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा नागरिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करना शामिल है। देश की विभिन्न सार्वजनिक सेवा विभागों में लगे सिविल सेवा के इन्ही अधिकारियों के काम को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिविल सेवकों के लिए देश की प्रशासनिक मशीनरी को सामूहिक रूप से और नागरिकों की सेवा के प्रति समर्पण के साथ चलाने की भी याद दिलाता है। सिविल सेवा शब्द सबसे पहले ब्रिटिश काल में आया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे। तब उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। इस व्यवस्था की नींव ब्रिटश अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई। लेकिन बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस द्वारा और अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन भारतीय इतिहास में सिविल सेवा की शुरुआत मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक कार्यों को संभालने के लिए की गई थी। कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन धीरे-धीरे यह सेवा प्रशासनिक मशीनरी के रूप में भी विकसित हुई। कालांतर में जैसे-जैसे कंपनी के क्षेत्रीय प्रभाव में विस्तार हुआ, वैसे-वैसे सिविल सेवकों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ीं और प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए उन्हें तैयार किया गया। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में राजधर्म, प्रशासनिक ढांचे, अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों के रूप में मिलता है। तब शासन में न्याय, कर-संग्रह, जनकल्याण, और दंड नीति पर विशेष बल दिया गया था। हमारे प्राचीन महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में राजधर्म, दंडनीति और राज्य व्यवस्था के उच्च आदर्शों का भी उल्लेख मिलता है। यही नहीं भारतीय सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक संचालन के लिए राजुक एवं महामात्र आदि अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यह अधिकारी न्याय, कर संग्रह, जन-कल्याण और राज्य की निगरानी जैसे कार्य करते थे। प्राचीन शिलालेखों में धम्म नीति का उल्लेख मिलता है, जो शासन में नैतिकता और लोकहित को प्रमुखता देता है। वहीं,गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। प्रशासनिक पदों में उपरिक, विषयपति, नगरपति, और ग्रामिक जैसे पदाधिकारी नियुक्त होते थे।स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार प्राप्त थे, जिससे शासन सुगठित रूप से चलता था। मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षिण भारत के साम्राज्य चोल, चेर, पाण्ड्य और विजयनगर साम्राज्य में संगठित प्रशासनिक तंत्र था।

प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के इतिहास में चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली अत्यंत विकसित थी। तब ग्राम सभाएं सक्रिय रूप से कर संग्रह, न्याय और विकास कार्यों में लगी रहती थीं। आज की प्रशासनिक व्यवस्था में काल की प्रशासनिक व्यवस्था परिलक्षित होती है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक संगठित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था, जिसमें आठ मंत्री विभिन्न विभागों का संचालन करते थे।इनमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, सचिव, पंडितराव, सेनापति, नायक एवं न्यायाधीश शामिल थे। उस काल में भी आज की ही तरह ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका संचालन ग्रामसभा करती थी। इसके बाद में तब के मुगल शासन में प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया गया। जिसमे न्यायपालिका, पुलिस और राजस्व प्रशासन को अलग-अलग विभागों में बांटा गया। राजस्व नीति में टोडरमल की व्यवस्था को ऐतिहासिक माना जाता है।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश के सिविल सेवकों के पहले बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था। देश के सिविल सेवकों को समर्पित इस प्रेरक भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था।

हमारे ऋषि...

डॉ. नीरज भारद्वाज

भगवान श्रीराम का ऋषि मुनियों के प्रति भक्ति भाव

हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते समय अपने साधु, संत, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों आदि को नहीं भूलना चाहिए। इन ऋषि-मुनियों आदि के ज्ञान, ध्यान, तप, योग, साधना आदि से ही ज्ञान परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच पाई। हमारी गुरूकुल व्यवस्था, तीर्थ स्थानों, पवित्र नदियों आदि के किनारे बैठे योगी साधकों ने अपने आशीर्वाद आदि से सामान्य जीव को ज्ञान दिया। विचार करें तो इसी ज्ञान परंपरा के चलते पशु-पक्षियों को भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। हमारे ऋषि-मुनि ज्ञान का अथाह सागर हैं। वह मौन से भी जीव को बहुत कुछ दे देते हैं। इन ऋषि-मुनियों का दर्शन ही जीवन को बदल देता है। एक विचार के अनुसार भगवान और देवताओं का धरा धाम पर अवतार लेकर आना भी ऋषि-मुनियों के यज्ञ, तप का ही फल है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रृंगी रिषिहि बहोरि बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।। अर्थात भगवान श्रीराम के जन्म के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ महर्षि श्रृंगी (ऋष्यश्रृंग) ने किया। राजा दशरथ के अनुरोध पर उन्होंने सरयू के तट पर यह यज्ञ संपन्न किया, जिसके बाद अग्निदेव ने खीर का प्रसाद दिया था। जिससे भगवान श्रीराम का प्राकट्य धरा धाम पर हुआ। भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र को जब हम रामचरितमानस के आधार पर जानते, समझते, पढ़ते और विचार करते हैं तो पाते हैं कि भगवान श्रीराम ने अपनी शिक्षा ऋषियों, मुनियों, संतों के पास पूरी की है। 'गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई' अर्थात जब भगवान श्रीराम गुरु वशिष्ठ के आश्रम (गुरु गृह) शिक्षा ग्रहण करने गए, तो उन्होंने बहुत कम समय (अल्प काल) में ही सभी तरह की विद्या और ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह सच्चे मन से गुरु की शरण में जाने के महत्व को दर्शाता है। शिक्षा प्राप्त करते हुए ही भगवान श्रीराम को बहुत सारे ऋषि-मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान श्रीराम को धनुष यज्ञ के समय अर्थात अपने विवाह में भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

भगवान श्रीराम ने चौदह वर्षों के वनवास के समय बहुत से महान ऋषियों-मुनियों के आश्रमों की यात्रा की और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान तथा दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वनवास के प्रारंभ में प्रयागराज पहुंचने पर श्रीराम सबसे पहले महर्षि भरद्वाज के आश्रम गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहि राम पद अति अनुरागा॥ तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना।। भरद्वाज ऋषि ने ही श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को चित्रकूट में निवास करने का सुझाव दिया था। चित्रकूट प्रवास के समय श्रीराम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा॥ देखि राम छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहिं आने॥ वाल्मीकि जी ने ही उन्हें वह स्थान दिखाया जहाँ उन्हें अपनी कुटिया बनानी चाहिए। चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद श्रीराम महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे।

विकास की ओर माओवाद मुक्त क्षेत्र

भारतीय इतिहास में 31 मार्च, 2026 का दिन सशस्त्र माओवाद के खात्मे के रूप में दर्ज हो चुका है। इस दिन देश ने माओवादी आतंक के विरुद्ध निर्णायक सफलता हासिल की। यह लोकतंत्र, सुशासन और विकास के उस व्यापक सोच की विजय है, जिसने वर्षों से हिंसा से जूझ रहे बस्तर को एक नई दशा और दिशा दी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एक स्पष्ट नीति और दृढ़ नेतृत्व को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने माओवाद के प्रति "शून्य सहनशीलता" और "विकास आधारित समाधान" की नीति अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल रणनीतिक स्तर पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया, बल्कि कई बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जवानों और स्थानीय लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। इस पूरे अभियान में हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बस्तर की जनता के सहयोग ने इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू संवाद और पुनर्वास रहा है। यह संदेश दिया गया कि जो लोग हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वार खुले हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन अपनाया। ऐसे लोग जो केवल हिंसा की भाषा समझते थे, उनके विरुद्ध सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई भी की। सुधाकर, बसवराजू जैसे शीर्ष माओवादी नेतृत्व को न्यूट्रलाइज करने से माओवादी आतंक की कमर टूट गई। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्ययोजना बनाकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया। सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचीं, जहां कभी शासन की उपस्थिति नहीं थी। पिछले ढाई साल में डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 525 गांवों में "नियद नेल्ला नार" योजना के अंतर्गत 17 विभागों के माध्यम से 25 हितग्राही मूलक और 18 सामुदायिक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा रहा है।

विष्णु देव साय

जरा हटके

अक्षय तृतीया का अक्षय दिन

अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय (नाश) न हो । अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है कोई भी शुभ कार्य का प्रारम्भ किया जा सकता है । विक्रम सम्वत का वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया खास हैं जो कभी क्षय नहीं होती इसीलिए अक्षय तृतीया कहलाती हैं । हर शुभ कार्य में उत्तम मानी जाती है, अबूझ मुहूर्त कहलाती है। अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। जैन परम्परा में इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस तृतीया को ही जैन परम्परा में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ की बारह मास की अ-पचक्खी बिना अन्न जल की तपस्या का प्रपौत्र श्रेयांस के हाथों अकस्मात पारणे का सुसंयोग मिला । वह तब से लेकर अनवरत आज तक एकांतर वर्षी तप के पारणे के रूप में हर वर्ष सोत्साह मनाने का दिन माना जाने लगा। वैसे अटूट अभंग का हमारी मान्यता में सदा ही शुभ का योग माना जाता है। देवी-देवताओं की पूजा अर्चना व शुभ कार्यों में अक्षत यानी अभंग चावल का प्रयोग। इसीलिए तिथि के अक्षय गुण के कारण इस अक्षय तृतीया को शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है । इस अक्षय तिथि की ही क्या बात करें कई बातें हैं तीन-तीन की जो अक्षय की तरह शुभ हैं जैसे ज्ञान-दर्शन-चारित्र , अध्यात्म में उत्तम, पवित्र हैं । हर परिस्थिति में देव-गुरु-धर्म इनका स्मरण सम्बल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं । मन-वचन-काया इनका महत्व तो शास्त्रों ने पग-पग पर गाया है। भगवान् ऋषभ के समय लोगों का बौद्धिक विकास नहीं के बराबर था । जितना बताया जाता था वे उतना ही समझते थें । आस- पास की बात उनके चिन्तन के बाहर थी । खेती पकने के बाद उसे काटकर अनाज निकालने की विधि स्वयं ऋषभ ने उन्हें बतलाईं । लोग अनाज निकालने लगे । अनाज पर बैलों को घुमा - घुमा कर अनाज और भूसे को अलग- अलग करते , पर बैलों को भूख लगने पर वे उसी अनाज को खानें लगें । लोग घबराएं और सोचने लगे कि ये अनाज खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे ? शाम को ऋषभ के पास आए । वे ऋषभ को बाबा के नाम से पुकारते थें । कहने लगे- बाबा! अनाज तो बैल खा जाएंगे फिर हमारे लिए क्या बचेगा । बाबा ने घास कि रस्सियों की छींकी बनाकर कहा- ऐसी छींकी लगा दो, फिर नहीं खाएंगे। दूसरे दिन सभी लोगों ने छींकी लगा दी, बैलों के मुंह छींकी से बन्द हो गए । दिन-भर कुछ भी नहीं खा सकें किसान खुश थे । आज एक दाना भी फालतू नहीं गया । शाम को उन बैलों के आगे चारा आदि रख दिया, फिर भी उन्होंने नहीं खाया । अब क्या होगा? सब बाबा के पास पहुँचे, अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए बोले- बाबा बैल तो मर जाएंगे , उन्होंने खाना- पीना छोड़ दिया हैं ।

› प्रदीप छाजेड़

या फिर सरकार...

कमलेश पांडेय

प्रधानमंत्री ने महिला कोटा संशोधन बिल सम्बन्धी अपनी सरकार की नाकामियों को विपक्ष के मत्थे मढ दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया राष्ट्र के नाम संदेश मुख्य रूप से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े कतिपय संशोधन के असफल होने के बाद आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। यह संदेश राजनीतिक रूप से विपक्ष को निशाना बनाने और अपनी सरकार की छवि को मजबूत करने का प्रयास था। लेकिन उन्हें ठंडे दिमाग से देश को जवाब देना चाहिए कि जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्राप्त है तो फिर संसद और विधान मंडलों में इसे अविलंब लागू करने के लिए सरकार परिसीमन का लॉलीपॉप क्यों थमा रही है?

या फिर सरकार तदर्थ व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है कि राजनीतिक दल घोषित आरक्षण के मुताबिक ही टिकट वितरण करेंगे, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा? यही नहीं तमाम राजनीतिक दलों के सांगठनिक पदों में भी यह आरक्षण लागू होगा। जरा सोचिए, गलत तो नहीं कहा! बात छोटी थी, गलती बीजेपी एनडीए सरकार की थी, लेकिन विपक्ष को आरोपों के कठघरे में खड़ा करके मुद्दे को तिल से ताड़ बनवा दिया। जैसे इसी काम में महारत हासिल हो! गंभीर सवाल है कि जब आप कांग्रेस और समाजवादी राजनीति के सियासी पीच पर जाकर बॉलिंग/बैटिंग कीजिएगा तो राष्ट्रवादी परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। आप भ्रम में हैं कि ओबीसी/दलित/अल्पसंख्यक आपको हाथोंहाथ लेंगे, मौका मिलते ही सियासी धोबिया पाट पर ऐसे पिटेंगे, जैसे 12 वर्षों में पहली बार मौका मिलते ही संसद में पीट दिया। आपका बहुमत है, लेकिन दो तिहाई बहुमत आप जुटा नहीं पाए, जबकि संसद ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक सांसदों से अटी पड़ी है। स्वाभाविक सवाल है कि कहाँ गया आपका अति पिछड़ी जाति से होने का गुरूर! जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद को पिछड़ा/अति पिछड़ा कहे, वह राष्ट्र मानसिक धरातल पर कितना पिछड़ा होगा! तभी तो अपने पड़ोसी देशों के एजेंडे पर भारत थिरकता है, क्योंकि पिछड़ी मानसिकता से दुनिया आखिर उम्मीद ही क्या करेगी? गरीबी चेहरे से बोलती है, लेकिन संवैधानिक गरीबी तो 7-8 दशकों से लाइलाज है। जिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को स्वर्गिक सुविधाएं नसीब हैं, वह कागज में पिछड़ा बना रहता है। यह बहुमत का नंगानाच है, भारत की सभी परेशानियों की जड़ है। कितनी अटपटी बात है कि जब आप ओबीसी, दलित, पसमांदा वोट बैंक के लिए, सबकुछ करने को ततपर हैं, तब गिने चुने सांसद भी मैनेज नहीं हुए तो आम जनमानस जिसमें समाजवादी जातिवादी, दलितवादी, अल्पसंख्यक-वादी और सवर्ण विरोधी इतना जहर घुल गया है कि अब आपकी भाजपा उन्हें पटाने के चक्कर में कांग्रेसी दुर्गति को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ऐसा इसलिए कि यूजीसी बिल से आपके वफादार दिल से खिसके और महिला संशोधन बिल, परिसीमन बिल के चक्कर में ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय जमात! अब आप खुद सोचिये, सच्चाई के सियासी धरातल पर कहाँ खड़े हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं कांग्रेसी मौत मरेगी यानी पिछड़ेगी क्योंकि कांग्रेस से भागे सवर्णों ने ही तो आपका राजनीतिक घर बसाया है।

इस तल्ख सच्चाई की काट ढूंढिए, अन्यथा इतिहास खुद को दोहराएगा ही। राजद और सपा-बसपा का पतन भी तो इसी राजनीतिक संतुलन को साधने के चक्कर में हुआ! अब मुद्दे पर लौटते हैं! मोदी जी का यह संबोधन लोकसभा में विधेयक गिरने के तुरंत बाद शनिवार को हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल जैसे दलों को परिवारवाद और महिलाओं के हक छीनने का आरोप लगाया।

भारत को 8 विकेट से हराया ■ लौरा वोल्वार्ट-सुने लूस की शतकीय साझेदारी

साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की दूसरे टी-20 में जीत

मुकाबला

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

डरबन में खेले गए इस मुकाबले में शेफाली वर्मा के अर्धशतक के बावजूद मिडिल और लोअर ऑर्डर के फ्लॉप प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। साउथ अफ्रीका ने 148 रन का टारगेट 17.1 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीकी टीम ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान लौरा वोल्वार्ट और सुने लूस ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की शानदार पार्टनरशिप की, जिसने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

शेफाली ने मैच की चौथी ही गेंद पर छक्का जड़ा और सेखुखुने के दूसरे ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर 14 रन बटोरे। हालांकि, उन्हें 28 के निजी स्कोर पर जीवनदान भी मिला, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने 31 गेंदों में करियर की 15वीं फिफ्टी पूरी की।

वह 57 रन बनाकर म्लाबा की गेंद पर आउट हुईं। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने स्पिन और सीम दोनों से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। टुमी सेखुखुने और क्लो ट्रायोन ने 3-3 विकेट लिए। वहीं, नॉनकुलुलेको म्लाबा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिया। भारतीय पारी 147 रन पर सिमट गई।

■ शेफाली वर्मा ने 57 रन की पारी खेली।

148 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को लॉरा वोल्वार्ट और सुने लूस ने ठोस शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की। वोल्वार्ट ने अपनी 15वीं टी-20 फिफ्टी लगाई, वहीं लूस ने पिछली 10 पारियों में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। हालांकि, दोनों जीत से पहले आउट हो गईं, लेकिन ताजमिन ब्रिट्स और एनेरी डर्कसन ने 17 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी।

शेफाली के 57 रन, फिर 48 रन पर 8 विकेट गिरे

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही थी। 13वें ओवर तक टीम का स्कोर 2 विकेट पर 99 रन था और वह 160 से अधिक के स्कोर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारत ने महज 48 रन के भीतर अपने आखिरी 8 विकेट गंवा दिए। शेफाली वर्मा ने 57 रनों की पारी खेली, जबकि डेब्यू कर रही अनुष्का शर्मा ने 28 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका।

शेफाली ने 100वें मैच में लगाई फिफ्टी

22 साल की शेफाली वर्मा ने इस मैच के साथ ही अपने 100 टी-20 इंटरनेशनल मैच पूरे कर लिए। उन्होंने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था। अपने इस माइलस्टोन मैच में उन्होंने आक्रामक बैटिंग की।

आईपीएल 2026 के बीच पत्नी अनुष्का संग वृंदावन पहुंचे विराट

5 महीनों में तीसरी बार लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद

नई दिल्ली, एजेंसी

आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे आरसीबी के दिग्गज बैटर विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आईपीएल के बीच किंग कोहली पत्नी अनुष्का के साथ अक्षय तृतीया पर वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे थे। कोहली के एक फैन पेज ने इसका वीडियो शेयर किया है। इस दौरान दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में दर्शन किए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। दरअसल, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन के 'श्री हित राधा केलि कुंज' आश्रम जाकर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। वहां उन्होंने महाराज जी के साथ 'एकांतिक वार्तालाप' (निजी आध्यात्मिक चर्चा) में भाग लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कपल को आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर शांति से गुरु के प्रवचन सुनता देखा गया। अक्षय तृतीया के खास अवसर पर एक खास कार्यक्रम में शामिल होकर विरुष्का ने भक्ति भाव से आशीर्वाद लिया।

इस दौरान एक वीडियो में किंग कोहली को गले में तुलसी की माला पहने हुए देखा जा रहा है, जबकि अनुष्का शर्मा सफेद रंग के संपल सूट में नजर आईं। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में विराट ने 19 रन बनाए थे। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का अगला मुकाबला 24 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) से है। इस बीच मिले कुछ दिनों के ब्रेक का इस्तेमाल विराट ने मानसिक शांति और भक्ति के लिए किया।

'पति पत्नी और वो दो' में 3 एक्ट्रेसेस से रोमांस करेंगे आयुष्मान, पहले पोस्टपोन हो चुकी मूवी

साल की 6वी सीक्वल फिल्म का टीजर रिलीज

नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का टीजर रिलीज हो गया है। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जबरदस्त कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरी नजर आ रही है।

यह इस साल की 6वी सीक्वल फिल्म होगी। इससे पहले बॉर्डर 2, मर्दानी 3, वध 2, द केरला स्टोरी 2, गिनी वेड्स सनी जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। हालांकि बॉर्डर 2 के अलावा इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि इससे पहले ये होली के मौके पर 4 मार्च को रिलीज होनी थी। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा था। मेकर्स ने पहले इस फिल्म को होली के मौके पर 4 मार्च 2026 को रिलीज करने का फैसला किया था। हालांकि, अब इसकी रिलीज को टाल दिया गया है। नई घोषणा के मुताबिक, फिल्म अब 15 मई 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म को टी-सीरीज और बीआर स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसके प्रोड्यूसर भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा हैं, जबकि जूनो चोपड़ा फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 2019 में आई 'पति पत्नी और वो' की फ्रेंचाइजी का दूसरा हिस्सा है। पिछले पार्ट में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे लीड रोल में थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस बार मेकर्स ने पूरी स्टार कास्ट बदल दी है। हालांकि, डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ही हैं।

टीजर में फिल्म को 'पतिवर्स' (Pativerse) के रूप में पेश किया गया है, जो पुरानी यादें ताजा करता है।

66 सीक्वल में इस बार आयुष्मान खुराना की एंट्री से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। आयुष्मान अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री देखना दिलचस्प होगा। मेकर्स का दावा है कि इस बार कहानी में कई फ्रेश ट्विस्ट और मजेदार सिचुएशंस होंगी, जो पिछली फिल्म से काफी अलग और बड़ी होंगी।

तीन एक्ट्रेसेस के बीच फंसे आयुष्मान

टीजर में आयुष्मान खुराना 'प्रजापति पांडे' के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस बार उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन का लेवल काफी ज्यादा है। आयुष्मान एक या दो नहीं, बल्कि तीन महिलाओं के बीच फंसे हुए हैं। फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं। टीजर में विजय राज एक पुलिस वाले के रोल में दिख रहे हैं, जो कॉमेडी को और बढ़ा रहे हैं।

प्रेग्नेंसी में भी काम जारी रखेंगी दीपिका पादुकोण

राका फिल्म के एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगी

नई दिल्ली। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। खास बात यह है कि इस अवस्था में भी दीपिका अपने काम से ब्रेक नहीं लेंगी और आने वाली फिल्मों की शूटिंग जारी रखेंगी।

रविवार को दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी 'दुआ' के साथ एक फोटो शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, दीपिका अपनी प्रेग्नेंसी के बीच भी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरी अहमियत दे रही हैं। फिलहाल वे फिल्म 'राका' की शूटिंग कर रही हैं। सोर्स ने बताया, दीपिका फिल्म 'राका' के लिए कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही हैं। वे अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगी। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक कोलाज या सिंगल फोटो के बजाय एक बेहद ही सिंपल और प्यारी तस्वीर शेयर की है। इसमें उनकी बेटी दुआ पादुकोण सिंह ने एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़ी हुई है। फोटो में रणवीर और दीपिका के हाथ अपनी बेटी को थामे हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए दीपिका ने कैप्शन में किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ बुरी नजर से बचाने वाला (Evil Eye) इमोजी लगाया है।

दीपिका और रणवीर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद नवंबर 2018 में इटली में शादी की थी। शादी के करीब 6 साल बाद सितंबर 2024 में दीपिका ने अपनी पहली बेटी दुआ को जन्म दिया था। अब दुआ डेढ़ साल की होने वाली है और जल्द ही बड़ी बहन बनने वाली है। कपल के इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस लगातार बधाइयां दे रहे हैं।

तेल-गैस सप्लाई रुकी, फैक्ट्रियां ठप, आर्थिक दबाव में कई देश, एक्सपर्ट बोले- ये आर्थिक संकट सुनामी जैसा

ईरान युद्ध से धीमी हुई एशिया की रफ्तार

संकट

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध एशिया-प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा असर डाल रहा है। शुरुआत में लगा था कि तेल और गैस की कमी का असर धीरे-धीरे दिखेगा, लेकिन हकीकत में कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर अचानक बड़ा झटका लगा है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना कोविड जैसे बड़े संकट से कर रहे हैं। भले ही जल्द शांति समझौता हो जाए, लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर इसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। आने वाले महीनों में उड़ानें रद्द होने, खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने, फैक्ट्रियों के रुकने, सामान की सप्लाई में देरी और बाजारों में रोजमर्रा की चीजों की कमी देखने को मिल सकती है। इसमें प्लास्टिक बैग, इंस्टेंट नूडल्स, वैक्सीन, सिरिंज, लिपस्टिक, माइक्रोचिप और स्पोर्ट्सवियर जैसी चीजें भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट के रास्तों से व्यापार कुछ और हफ्तों तक बाधित रहा, तो कई देशों में हालात बिगड़ सकते हैं, अशांति फैल सकती है और मंदी आ सकती है। कई कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं और सरकारें महंगाई को काबू में रखने के लिए भारी कर्ज ले रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, साल के अंत तक एशिया में लाखों लोग गरीबी में जा सकते हैं। वियतनाम के किसान, भारत के मजदूर, श्रीलंका के होटल मालिक, फिलीपींस के ड्राइवर और हांगकांग-सिंगापुर के कारोबारी सबकी चिंता बढ़ी हुई है। कई सरकारें बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हालात संभालना मुश्किल हो रहा है।

■ तेहरान की एक बिल्डिंग पर होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने के ईरानी इरादे को दिखाता एक म्यूरल।

चीन जैसे अमीर देशों पर असर थोड़ा कम होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन हैं, लेकिन बाकी एशिया में हालात ज्यादा खराब हैं। कई देशों की असली स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है।

■ ढाका की एक गार्मेंट फैक्ट्री में काम करती महिलाएं। ईरान युद्ध के कारण उत्पादन और शिपमेंट में बड़े स्तर पर बाधाएं देखी जा रही हैं।

संकट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सप्लाई खतरे में

ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारी संकट आ गया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होते ही एशिया में ट्रक, जहाज और विमान प्रभावित होने लगे। मार्च में दुनिया भर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जो पहले के मुकाबले दोगुनी हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर एशिया-प्रशांत में दिखा। मिडिल ईस्ट के रास्ते उड़ान भरने वाली एयरलाइंस ने दुबई जैसे बड़े हब के लिए उड़ानें तुरंत रोक दीं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई और सप्लाई भी खतरे में पड़ गई, जिससे एयरलाइंस ने कई रूट बंद कर दिए। क्वांटस, एयर न्यूजीलैंड, लायन एयर, वियेटजेट, एयरएशिया, एयर इंडिया और कैथे पैसिफिक जैसी कई कंपनियों ने सेवाएं कम की हैं। मलेशिया की बाटिक एयर ने तो 35% उड़ानें घटा दीं ताकि दिवालिया होने से बच सके।

भारत से श्रीलंका तक आर्थिक संकट का खतरा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक, दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग हर जगह धीमी हो रही है क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई बाजार से बाहर हो गई है। मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल-गैस रुकने से पूरे एशिया की सप्लाई चेन हिल गई है।

एशिया-प्रशांत पर सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र मिडिल ईस्ट के तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, यहां की अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी है और पहले से ही ऊर्जा की मांग ज्यादा थी जबकि सप्लाई कम पड़ रही थी। यहां तक कि अगर होर्मुज की समस्या कल ही ठीक भी हो जाए तो भी तेल और गैस की सप्लाई को पहले जैसे स्तर पर आने में सालों लग सकते हैं।

एटोक (फिलीपींस) में एक किसान अपने गोभी के खेत को देखता हुआ। किसान ने फसल काटने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि डिलीवरी के लिए बढ़ती ईंधन लागत के कारण घाटे में फसल बेचने से बेहतर है कि वह इसे खेत में ही सड़ने दे। तस्वीर मार्च की है।

दौरा : भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना यात्रा का मुख्य लक्ष्य, विदेश मंत्रियों से मुलाकात की

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सऊदी अरब पहुंचे अजीत डोभाल

नई दिल्ली, एजेंसी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास हालात बिगड़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

रविवार को रियाद पहुंचने पर उनका स्वागत सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल-साती ने किया। इसके बाद डोभाल ने ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल-ऐबान से मुलाकात की। भारतीय दूतावास के अनुसार, इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त किया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के अनुसार, जहाज ने चेतावनी के बावजूद रुकने से इनकार किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में भी उछाल देखा गया।

इन सबके बीच अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में पहली दौर की वार्ता हो चुकी है। अब दूसरे दौर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है।

ऊर्जा सुरक्षा पर खास जोर

डोभाल की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में हालात बदलने के असर को समझने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य रहा।

भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। इसी कारण भारत प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ लगातार संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए है।

सभी की उम्र 1 से 11 साल थी, पत्नी को भी गोली मारी, हालत गंभीर

अमेरिका : शख्स ने अपने 7 बच्चों समेत 8 की हत्या की

लुइसियाना, एजेंसी

अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवेपोर्ट शहर में एक शख्स ने 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इनमें से 7 उसके ही बच्चे थे। अमेरिका में इस साल की यह सबसे बड़ी मास शूटिंग की घटना मानी जा रही है।

CNN के मुताबिक यह घटना रविवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय के मुताबिक) वेस्ट 79वीं स्ट्रीट के 300 ब्लॉक में हुई। आरोपी का नाम शमार एल्किंस (31 साल) है। पुलिस ने बताया कि 7 बच्चों को घर के अंदर गोली मारी गई, जबकि एक बच्चे को छत पर गोली लगी, जब वह जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था।

■ मारे गए बच्चों के साथ आरोपी शमार एल्किंस। (फाइल फोटो)

हमले में असॉल्ट-स्टाइल हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसे घरेलू विवाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है।

आरोपी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी। इसके बाद वह दूसरे घर गया, जहां उसने आठ बच्चों और एक अन्य महिला को गोली मारी। दूसरी महिला, जो मारे गए आठवें बच्चे की मां थी, उसकी हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 31 साल का शमार एल्किंस था, जो मौके से भाग गया था। उसने बंदूक की नोक पर एक कार लूटकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने के दौरान पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

आरोपी ने पत्नी को भी गोली मारी, हालत गंभीर

पुलिस ने मृतकों की पहचान जयला एल्किंस (3), शायला एल्किंस (5), कायला प्यू (6), लैला प्यू (7), मरकेडॉन प्यू (10), सारियाह स्नो (11), खेडारियन स्नो (6) और ब्रेलॉन स्नो (5) के रूप में की है। इस हमले में 13 साल का लड़का भी घायल हुआ, जो जान बचाने के लिए घर से भागा और छत से कूद गया। श्रेवेपोर्ट पुलिस के मुताबिक मारे गए बच्चों में तीन लड़के और पांच लड़कियां थीं, जिनकी उम्र 3 से 11 साल के बीच थी।

यूपी में 64 आईएएस का ट्रांसफर, 10 डीएम बदले

तबादला

मंत्री से टशन, किंजल सिंह को हटाया, मनीष बंसल आगरा डीएम, ये मुख्य चुनाव आयुक्त के दामाद

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ। योगी सरकार ने रविवार देर रात 64 IAS अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें 12 महिला अफसर हैं। 10 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से अनबन के बाद परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। किंजल सिंह की 7 महीने पहले ही परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई थी। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2010 बैच के IAS आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त बनाया है। वहीं, यूपी पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार को हटा दिया गया है। उन्हें फिलहाल यूपी में नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।

स्मार्ट मीटर विवाद की वजह से इन पर सवाल उठ रहे थे।औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार से एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। सरकार ने लंबे मंथन के बाद आईएएस की तबादला सूची जारी की। 8 डीएम को एक जिले से हटाकर दूसरे जिले का जिलाधिकारी बनाया है। सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा का डीएम बनाया है। IAS मनीष बंसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। बंसल की पत्नी मेधा रूपम नोएडा की जिलाधिकारी हैं। 7 डीएम को अन्य विभाग में तैनाती दी गई है। लखीमपुर खीरी की DM दुर्गाशक्ति नागपाल को पदोन्नति के बाद देवीपाटन मंडल का मंडलायुक्त बनाया है। आगरा के DM अरविंद मल्लप्पा बांगरी को CM योगी का विशेष सचिव बनाया गया है। बुलंदशहर की डीएम श्रुति को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया है।

इन 7 अफसरों को पहली बार मिली जिले की कमान

- 2014 बैच के आईएएस और सीएम योगी के विशेष सचिव ब्रजेश कुमार का ट्रांसफर औरैया के डीएम पद पर किया है।
- 2015 बैच के आईएएस एवं झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव का ट्रांसफर शामली जिलाधिकारी के पद पर किया है।
- 2016 बैच के आईएएस अभिषेक गोयल का ट्रांसफर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के विशेष सचिव से हमीरपुर के डीएम पद पर किया है।
- 2016 बैच के आईएएस इंद्रजीत सिंह का ट्रांसफर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव से डीएम सुल्तानपुर के पद पर किया है।
- 2016 बैच की आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग का ट्रांसफर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के विशेष सचिव से श्रावस्ती डीएम के पद पर किया है।
- 2016 बैच के नितिन गौड़ का ट्रांसफर हापुड़-पिलखवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से अमरोहा के डीएम पद पर किया है।
- 2016 बैच की आईएएस सरनजीत कौर ब्रोका का ट्रांसफर महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक पद से रायबरेली डीएम के पद पर किया है।
- 2014, 2015 और 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों को पहली बार डीएम के पद पर पोस्टिंग देनी थी। इसके चलते कुछ जिलों के डीएम हटाए गए हैं।
- 2014, 2015 और 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों को पहली बार डीएम के पद पर पोस्टिंग देनी थी। इसके चलते कुछ जिलों के डीएम हटाए गए हैं।

पांच जिलों के सीडीओ बदले

देवरिया की संयुक्त मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा को हापुड़, सुल्तानपुर की संयुक्त मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला को सुल्तानपुर, आजमगढ़ के संयुक्त मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवता को बहराइच, चित्रकूट की संयुक्त मजिस्ट्रेट पूजा साहू को अमेठी और गाजीपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सबन्नवाड को झांसी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया है।

इन 8 डीएम को फिर मिली जिले की कमान

उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी को झांसी का डीएम बनाया है। सुल्तानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर का डीएम बनाया है। शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर का डीएम बनाया है। अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर का डीएम बनाया है।

हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीना को उन्नाव का डीएम बनाया है। मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को लखीमपुर खीरी का डीएम बनाया है। औरैया के डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी को मैनपुरी का डीएम बनाया गया है। सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा का डीएम बनाया है।

पिता के निधन के 6 दिन बाद मृदुल चौधरी का ट्रांसफर

झांसी के डीएम मृदुल चौधरी का ट्रांसफर उनके पिता धनीराम की मृत्यु के छह दिन बाद ही हो गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में उनके पिता का गत सप्ताह निधन हो गया था। पिता की तेरहवीं से पहले उनका ट्रांसफर हो गया है। उन्हें पर्यटन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

योगी सरकार में पहला मौका है, जब किंजल सिंह को ऐसी पोस्टिंग मिली है। वे कानपुर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, पंचायती राज विभाग की निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक और परिवहन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ही रही हैं। हालही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2010 बैच के आईएएस आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त बनाया गया है।

फास्ट न्यूज

स्टाफ की कमी, नहीं चालू हो पा रही नई मॉर्चरी

लखनऊ । लखनऊ में पोस्टमॉर्टम के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कभी-कभी पूरा दिन भी बीत जाता है। इससे लोगों को राहत देने के लिए KGMU में नई मॉर्चरी बनवाई गई थी। उसे करीब 2 साल पहले 2024 में हैंडओवर भी किया जा चुका है, लेकिन अभी मॉर्चरी चालू नहीं हुई। दरअसल, नई मॉर्चरी को एक्टिव करने के लिए कम-से-कम 15 मैन पावर की जरूरत है। औजार सहित कई संसाधनों की जरूरत है। मार्च में स्वास्थ्य महानिदेशक तरफ से एक आदेश जारी कर कहा गया कि प्रदेश के सभी पोस्टमॉर्टम हाउस में सभी सुविधाएं जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएं।

महिला आरक्षण बिल पर विशेष सदन बुलाया

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम में महिला आरक्षण का प्रस्ताव गिरने पर निंदा प्रस्ताव आएगा। इसके लिए 23 अप्रैल को सदन का आयोजन होगा। मेयर सुषमा खर्कवाल की तरफ से नगर आयुक्त गौरव कुमार को भेजे गए पत्र में विशेष सदन बुलाया गया है। हालांकि पत्र में एजेंडे से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इसको लेकर कांग्रेस और सपा पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मेयर सुषमा खर्कवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा- मुद्दा देश की आधी आबादी के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है। ऐसे अहम मुद्दे पर प्रस्ताव का गिरना चिंताजनक है।

काकोरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में चोरी

दुबग्गा । लखनऊ के काकोरी स्थित मौंदा गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सूने घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। परिवार मैहर दर्शन के लिए गया था। घरवाले रविवार रात घर लौटे तो घटना का पता चला। चोरों ने घर के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। गांव के पीड़ित इंजीनियर राजपाल यादव ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया- मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। शुक्रवार को परिवार के साथ मध्य प्रदेश के मैहर में माता के दर्शन के लिए गया था। तीन दिन घर में कोई नहीं था, उसी दौरान चोरी हो गई।

यूपीआईटीएस 2026 को बनाया जाएगा सशक्त सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, विभागों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

यूपीआईटीएस 2026 की तैयारियों का लिया जायजा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन सचिवालय के सी-ब्लॉक स्थित सभा कक्ष में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चतुर्थ संस्करण की तैयारियों की अद्यतन प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इन्वेस्ट यूपी, कृषि विपणन, विदेश व्यापार तथा यूपीएलसी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में ट्रेड शो की तिथियां 25 से 29 सितम्बर 2026 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों एवं विक्रेताओं को पूर्व नियोजन

में सुविधा मिल सके और आयोजन की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सके। यह भी तय किया गया कि इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्ष के पैमाने पर ही किया जाएगा, लेकिन विभागों को निर्देश दिए गए कि वे पारंपरिक प्रदर्शनी के बजाय अपनी उपलब्धियों को अधिक प्रभावी एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष ट्रेड शो का प्रमुख फोकस "जनता तक उपलब्धियों का प्रभावी संप्रेषण" होगा। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मीडिया, केंद्रीय

प्रतिनिधियों एवं विशिष्ट अतिथियों का ध्यान आकर्षित हो सके। बैठक में स्टॉल आवंटन एवं शुल्क संरचना पर भी निर्णय लिया गया। स्टॉल दरें 7,500 से 8,000 रूपये के बीच निर्धारित की गई हैं। दो तरफ खुले स्टॉल पर 10 प्रतिशत तथा तीन या चार तरफ खुले स्टॉल पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा। साथ ही, इस बार निजी क्षेत्र एवं छोटे कॉरपोरेट्स को भी पर्याप्त अवसर और दृश्यता प्रदान करने के निर्देश दिए गए, ताकि वे भी इस मंच का लाभ उठा सकें।

युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "सीएम युवा" पवेलियन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए डेयरी, उद्योग, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागों को नवाचार आधारित व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विशेष रूप से एनसीआर एवं गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने की प्रेरणा मिल सके। बैठक में एक्सपो मार्ट में विभागों को आवंटित हॉल एवं क्षेत्रफल की जानकारी भी साझा की गई तथा सभी विभागों को अपने-अपने सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी उत्पादकों को अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए, ताकि यह आयोजन उत्तर प्रदेश का एक सशक्त सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन सके।

केकेसी में यूजी की 4000 सीटों पर होगा एडमिशन

31 मई तक ऑनलाइन करें एप्लाई, एलयू में 100 है फीस

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय और KKC में सत्र 2026-27 के लिए यूजी(अंडर ग्रेजुएट) कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। LU में समर्थ पोर्टल के माध्यम से 17 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई है। विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड (मान्यता प्राप्त) महाविद्यालयों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहले LURN रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। वहीं, KKC में भी एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए LURN के बाद कॉलेज की ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन प्रक्रिया की जा सकेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई है। LU की साइट पर लर्न रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के UG कोर्स के अनुसार अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें प्रोग्राम का चयन, एजुकेशनल डिटेल भरना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क

जमा करना शामिल है। इसके अलावा लखनऊ के सबसे बड़े एडेड कॉलेज, श्री जय नारायण पीजी डिग्री कॉलेज (KKC) में भी 4 हजार से ज्यादा सीट पर एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। यहां भी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। KKC के प्रवक्ता प्रो. विजय राज ने बताया कि बीए और बीकॉम की 1080, बीएससी की 1160, एलएलबी की 320, बीकॉम ऑनर्स की 600, बीबीए में आईबी के 60 सीट, एमकॉम की 60, एप्लायड इकनॉमिक्स की 60, एमएससी फिजिक्स की 30 सीटें हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने फरियादियो से सीधे संवाद करते हुये सुनीं समस्याएं

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित 'जनता दर्शन' में जन-सेवा और प्रशासनिक संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि उप मुख्यमंत्री ने औपचारिकताओं को परे रखते हुए स्वयं एक-एक फरियादी के पास जाकर, उनसे सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को अत्यंत आत्मीयता के साथ सुना। प्रदेश के विभिन्न सुदूर जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी पीड़ा साझा की, जिस पर श्री मौर्य ने न केवल उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि समस्याओं के समाधान हेतु मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की। जनता दर्शन के दौरान बांदा जनपद से आए रामदत्त और ओम प्रकाश ने भूमि से दबंगों द्वारा किए गए अनाधिकार कब्जे को हटवाने की गुहार लगाई। वाराणसी से आए विजय शर्मा ने गंभीर बीमारी के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता अनुदान और राजेंद्र कुमार ने जटिल भूमि विवाद के त्वरित निस्तारण का आग्रह किया। बदायूं जिले से आए फरियादियों की संख्या भी

पर्याप्त रही, जिसमें राम विलास ने वैध विद्युत कनेक्शन होने के बावजूद दर्ज हुए मुकदमे की जांच कराने, चंद्रपाल ने बिजली संबंधी अन्य प्रकरणों और राम अवतार शाक्य ने अपनी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का पत्र दिया, साथ ही, बलरामपुर के राम अक्षयबर ने असाध्य रोग के इलाज के लिए आर्थिक मदद, फर्रुखाबाद की प्रेमवती शाक्य व सीतापुर के दीपू ने आवास दिलाने और महोबा के दयाशंकर ने अपनी पट्टे की जमीन को दबंगों के चंगुल से छुड़ाने की व्यथा सुनाई। न तमाम प्रकरणों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने शासन की सक्रियता और संवेदनशीलता का परिचय दिया और कई जिलों के जिलाधिकारियों एवं (एसएसपी/एसपी) से दूरभाष पर सीधी वार्ता की और निर्देश दिये कि धरातल पर पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक

एबीवीपी ने भी सपोर्ट किया, छात्र बोले-वीसी जनरल डायर, पोस्टर लगाए

एलयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सपा और एनएसयूआई का हंगामा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बवाल हो गया है। फ्रीजर, वाटर कूलर, एसी खराब होने का आरोप लगाते हुए छात्र वीसी ऑफिस पहुंच गए। वे जबरदस्ती चैनल खोलते हुए अंदर घुस गए। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से उनकी नोकझोंक हुई। दोपहर 12 बजे के आसपास ABVP से जुड़े छात्रों ने प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने वीसी को जनरल डायर भी कहा। इसके बाद करीब 2 बजे सपा छात्र सभा से जुड़े छात्रों ने भी प्रदर्शन कर दिया। वे भी पानी, एसी, फीस बढोत्तरी की समस्या को लेकर वीसी से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

इसके बाद करीबन 3 बजे NSUI के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। NSUI अध्यक्ष सुधांशु राणा ने विश्वविद्यालय परिसर में दीवारों पर पोस्टर भी लगाए। अर्पण कुशवाहा ने कहा कि प्रवेश परीक्षा, शुल्क और परिणाम इन बिंदुओं पर हमारा संगठन छात्रों की आवाज उठाता है। परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया है इसलिए हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हैं। विश्वविद्यालय का हॉस्टल कैंटीन लाइब्रेरी सब कुछ

गैलरी में ताला लगाने पर भड़के एबीवीपी के छात्र

लखनऊ विश्वविद्यालय में ABVP के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पीने का पानी खराब है और उसका टीडीएस 500 तक पहुंच गया है, जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा किया।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे।

NSUI के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए, विश्वविद्यालय के दूसरे गेट का घेराव किया और यहां बैठकर नारेबाजी की।

'छात्रों के साथ जनरल डायर जैसा रवैया'

प्रदर्शन कर रहे उत्कर्ष सिंह ने कहा कि नए कुलपति जब से आए हैं, विश्वविद्यालय को प्राइवेट मोड में ले आए हैं। ऐसा लगता है कि जनरल डायर की यूनिवर्सिटी है। जो मन में आ रहा है वह कर रहे हैं। सुविधा कैसे दी जाएं इस पर कोई ध्यान नहीं है। बच्चों से कैसे पैसा लिया जाए बस इसी पर पूरा फोकस है। यहां पढ़ने वाले छात्र बहुत पैसे वाले घर से नहीं आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर घरों से आते हैं। अगर बहुत अमीर होते तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। 50% तक फीस में वृद्धि हो रही है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और जब तक यह वापस नहीं हो जाएगा विरोध जारी रहेगा।

पृष्ठ 01 का शेष...

केजरीवाल को कोट...

क्या अब यह हो सकता है कि जजों को वादकारी द्वारा तय अतिरिक्त परीक्षा पास करनी पड़े कि वे मामले की सुनवाई के योग्य हैं? क्या उन्हें वादकारी द्वारा बनाए गए मानकों के आधार पर पहले खुद को साबित करना होगा? ऐसे में जजों को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी संगठन के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया या उनके परिवार के सदस्य विधि पेशे में नहीं हैं।

अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता हेगड़े के 'अग्निपरीक्षा' वाले तर्क का संज्ञान लिया, लेकिन सवाल उठाया कि केवल प्रतिकूल परिणाम के डर से किसी आरोपी के कहने पर जज को ऐसी परीक्षा से क्यों गुजरना चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह जज को पक्षपाती साबित करने की कोशिश करे। अदालत ने कहा कि जब किसी मौजूदा जज पर आरोप लगाए जाते हैं, तब भी वही निष्पक्षता लागू होनी चाहिए। कोई भी राजनेता, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, बिना किसी ठोस साक्ष्य के जज के खिलाफ आरोप लगाकर संस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अदालत कक्ष को धारणाओं का मंच नहीं बनाया जा सकता।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा दुर्भाग्य से आज मुझे दो पक्षकारों के बीच विवाद नहीं, बल्कि एक पक्षकार और स्वयं मेरे बीच के विवाद पर निर्णय करना पड़ रहा है। वर्तमान आवेदनों को स्वीकार करना जज पर लगाए गए आरोपों को मान्यता देने जैसा होगा। जब ऐसी स्थिति आती है, तो यह अदालत अपने और संस्था के पक्ष में खड़ी रहेगी। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि साक्ष्य मांगने वाली फाइल साक्ष्यों के साथ नहीं, बल्कि इशारों और आरोपों के साथ आई।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, मैं इन आवेदनों को खारिज कर रही हूं क्योंकि मेरी शपथ संविधान के प्रति है और संविधान हमें बताता है कि निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते। मैं इस मामले की सुनवाई से नहीं हटूंगी।

अदालत में मुख्य ममले से जुड़े प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। प्रतिवादियों को शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत में 29 और 30 अप्रैल को मामले में बहस के लिए सूचीबद्ध किया है।

कैच-22 रणनीति पर...

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस मामले में मुझे ऐसी स्थिति में रखा गया है कि यदि मैं खुद को अलग करती हूं तो क्या होगा और यदि नहीं करती हूं तो क्या होगा। अगर उसे राहत नहीं मिलती है, तो वह कहेगा कि उसने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। अगर उसे राहत मिलती है, तो वह कह सकता है कि अदालत ने दबाव में आकर फैसला किया। वादकारी स्थिति को अपने पक्ष के अनुसार पेश कर सकता है।

राहुल की दोहरी नागरि...

कर्नाटक में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। उनकी याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास उन्होंने याचिका लगाई थी।

यहां से FIR का आदेश बदले जाने के बाद विग्नेश ने 18 अप्रैल को एक घंटे के भीतर X पर 2 पोस्ट किए थे। पहली पोस्ट में लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतिम स्थिति यह है— मामला स्वीकार किया जाता है। विग्नेश ने केस से जुड़े सभी लोगों को चेतावनी देते हुए लिखा, 'कृपया ध्यान दें कि यदि इस मामले के स्टेटस में कोई परिवर्तन होता है, तो मैं अपना अगला ट्वीट अपलोड करूंगा और उसमें सभी माफिया, अंडरवर्ल्ड, कार्टेल, सिंडिकेट और अवैध गठजोड़ों का पर्दाफाश करूंगा। विग्नेश की दूसरी पोस्ट में कोर्ट का स्टेटस बदलने का जिक्र है। उन्होंने रिश्वत लेने का जिक्र करते हुए लिखा कि कृपया उनसे ली गई धनराशि वापस कर दें। अन्यथा मैं इंटरसेप्ट की गई कॉल को सीधे ट्विटर पर अपलोड कर दूंगा। पूरी तरह तैयार रहें। आपको स्थायी रूप से जेल जाना होगा। विग्नेश ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है। किसकी इंटरसेप्ट कॉल है, किसने धनराशि दी है, इसका भी सीधे-सीधे जिक्र नहीं है।

'मोदी झूठों के सरदार...

उन्होंने कहा- अरे ये पश्चिम बंगाल रबींद्रनाथ टैगोर की जमीन है। बाबर की जमीन नहीं है। लेकिन ममता दीदी के कारण कोई लफंगा भी आकर बोल सकता है कि बाबर की मस्जिद बनाऊंगा। असम में ये बोलकर देखो। तुरंत थाने जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, रेल और प्लेन जैसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर 40 मिनट तक रोका गया। महंगाई और बिल पर धोखा: चुनाव के बाद गैस के दाम बढ़ने की चेतावनी दी और दावा किया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। BJP को बताया 'गुंडों का गैंग': पुराने अपराधी और CPM के लोग अब BJP में शामिल होकर नेता बन गए हैं। पुलिस पर भी केंद्र का नियंत्रण होने का दावा किया। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी: चुनाव से पहले दिल्ली के इशारे पर TMC कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित I-PAC (आई-पैक) का हेड ऑफिस सोमवार को बंद पाया गया। संस्थान के एचआर विभाग ने अपने कर्मचारियों को आगामी 11 मई तक छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए हैं।

'विजन इंडिया समिट'...

भुवनेश्वर में आयोजित तीसरा समिट "होलिस्टिक हेल्थ" यानी समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रहा। अखिलेश यादव ने कहा, "स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन का नाम है।" इस दौरान विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस और सामाजिक वातावरण के प्रभाव पर अपने विचार रखे। अखिलेश यादव ने समिट के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे "विभाजन की राजनीति" के खिलाफ हैं और सकारात्मक, विकासोन्मुख राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने AI के दुरुपयोग, साइबर फ्रॉड और डीपफेक जैसे खतरों को लेकर भी चिंता जताई और इसके लिए ठोस राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता बताई।

यूपी में फिर चली तबा...

सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और विकास कार्यों की निगरानी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी।इसके साथ ही कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने पर भी प्रशासन का ध्यान रहेगा।

ईशा प्रिया के कार्यभार संभालने के बाद अंबेडकरनगर जिले में प्रशासनिक कामकाज की नई शुरुआत होगी। आने वाले समय में जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा तेज होने की संभावना है।

अंबेडकरनगर में ...

अब उन्हें गाजीपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है।गाजीपुर में उन्हें नए प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों को संभालना होगा।

राजस्थान में एचपीसी...

इस घटना के बाद उनका दौरा स्थगित हो गया है। आग लगते ही पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान और आग लगने के कारणों का आकलन बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी HPCL की यह रिफाइनरी राजस्थान में नए बने जिले बालोतरा के पचपदरा में मौजूद है। करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4500 एकड़ (7200 बीघा) में बनी रिफाइनरी में विदेशों से मंगाए जाने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करने और उससे अलग-अलग प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहां सालाना 9 मिलियन टन कच्चा तेल साफ किया जा सकता है। HPCL रिफाइनरी के दो हिस्सों में आग लगी। इनके नाम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU) हैं। पाइप लाइन के जरिए आने वाला कच्चा तेल इन्हीं यूनिट में आता है। फिर उसे फिल्टर करके अलग-अलग यूनिट में भेजा जाता है।

राजस्थान की इस रिफाइनरी में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से पाइप लाइन के जरिए कच्चा तेल लाया जाएगा। मुंद्रा से इसकी दूरी करीब 487 किलोमीटर है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676